

राज्य (दिल्ली प्रशासन)

बनाम

आई.के. नांगिया और अन्य

23 अक्टूबर, 1979

[एस. मुर्तजा फजल अली और ए.पी. सेन, जे.जे]

प्रक्रिया, जारी - प्रक्रिया जारी करने के लिए परीक्षण - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 204 खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954, धारा 17(2) का दायरा - ऐसे मामले में जहां खाद्य पदार्थ का निर्माता एक कंपनी है, जिसने अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के तहत एक व्यक्ति को जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित किया है, क्या इसकी किसी शाखा के बिक्री प्रबंधक पर अधिनियम की धारा 7(1) के साथ पठित धारा 6(1)(ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जब शाखा में बेची गई खाद्य वस्तु अधिनियम की धारा 2(आइए) के अंतर्गत मिलावटी पाई जाती है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, धारा 17(2)- क्या, अधिनियम संख्या 34 ऑफ 1976 द्वारा नई धारा 17 की शुरुआत के बाद, जब कोई अपराध घटित होता है। एक कंपनी, जिसने धारा 17(2) के तहत एक जिम्मेदार व्यक्ति को नामित किया है, उप-धारा (2) के तहत नामित नहीं होने वाले कंपनी के किसी अन्य अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है। जब तक यह आरोप न हो कि अपराध ऐसे अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया था या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण किया गया था।

31 अगस्त, 1976 को, खाद्य निरीक्षक ने मेसर्स अमर प्रोविजन एंड जनरल स्टोर से 'पोस्टमैन' ब्रांड रिफाइंड मूंगफली तेल का एक नमूना उठाया, जिसे 20 अगस्त 1976 को मेसर्स गैंदा मुल हेम राज द्वारा बेचा/आपूर्ति किया गया था और 9 सितंबर 1976 की सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार इसे कैस्टरोइल (खाद्य तेल नहीं) की उपस्थिति के कारण मिलावटी पाया गया। भोजन की इस मिलावटी वस्तु की आपूर्ति/बेची मेसर्स अहमद कोमर भोय द्वारा दिल्ली में अपने बिक्री प्रबंधकों, जे.के.नांगिया और वाई.पी.भसीन के माध्यम से गैंदा मुल हेमराज को की गई थी।

23 जून 1977 को, दिल्ली प्रशासन ने धारा 7(1) सहपठित धारा 16(1)(ए) और धारा 17 के तहत (i) मेसर्स अहमेई उमर भोय अहमद मिल्स, बॉम्बे प्रसिद्ध ब्रांड पोस्टमैन मूंगफली तेल के निर्माता (ii) उनके वितरक मै. गैंदा मुल हेमराज, नई दिल्ली, एक साझेदारी फर्म, और इसके प्रबंध भागीदार मेलर चंद जैन; (iii) मेसर्स अमर प्रोविजन एंड जनरल स्टोर्स, नेताजीनगर मार्केट, नई दिल्ली और इसके मालिक अमरीक लाल, रिटेलर (iv) वाई.ए.खान, प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण, अहमद मिल्स को निर्माताओं द्वारा अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है, और (v) दो बिक्री प्रबंधक, एमआईएस की दिल्ली शाखा। अहमद कॉमर भोय, निर्माता, आई.के.नांगिया और वाई.पी. भसीन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 1978 द्वारा पाया कि दो बिक्री प्रबंधकों को छोड़कर सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला था और तदनुसार प्रक्रिया जारी की। उन्होंने उत्तरदाताओं के खिलाफ शिकायत को इस आधार

पर खारिज कर दिया कि "उन्हें संबंधित वस्तु के निर्माता से कोई सरोकार नहीं था, बल्कि उन्होंने केवल उसकी बिक्री को प्रभावित किया था"। दिल्ली प्रशासन ने बर्खास्तगी के खिलाफ पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन उसने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

विशेष अवकाश द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय -

अभिनिर्धारित किया : प्रारंभिक चरण में, यदि कोई मजबूत संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह मानने का कोई आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायालय के लिए यह कहना संभव नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था। [1020 सी-डी]

मौजूदा मामले में, शिकायत में लगाए गए आरोप प्रतिवादियों के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 (एल) (ए) के साथ पठित धारा 7 (1) के तहत अपराध करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। शब्द "इसके प्रभारी थे" और "इसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार" इतने व्यापक हैं कि इसमें दिल्ली में मेसर्स अहमद उमर भोय की सभी व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है, जिनका कार्यालय दिल्ली में है और दो प्रतिवादी बिक्री प्रबंधक हैं [1020 ई, जी-एच, 1021 ए]

बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह, [1978] 1 एससीआर 257; लागू किया।

2. वास्तव में मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 7(i) के तहत सीधे तौर पर उत्तरदायी है। निर्माता मेसर्स अहमद उमर भोय, बॉम्बे उत्तरदायी बन गए क्योंकि वे दिल्ली में अपने शाखा कार्यालय के माध्यम से सीधे

मिलावटी वस्तु बेच रहे थे। प्रतिवादी आई.के.नांगिया और वाई.पी.भसीन भी धारा 7 में "अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा" शब्दों के कारण उत्तरदायी बन गए, जिसमें उनके एजेंट और नौकर शामिल हैं। इसे देखते हुए, विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को प्रतिवादियों के खिलाफ शिकायत को खारिज नहीं करना चाहिए था। [1021 ई.पू.]

3. अधिनियम 34/1976 द्वारा शुरू की गई नई धारा 17 के स्पष्ट अर्थ पर, जब किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, जहां धारा 17(2) के तहत कोई नामांकन नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय था प्रतिबद्ध व्यक्ति व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाता है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और दंडित किया जा सकता है। धारा 17(2) के तहत किसी व्यक्ति के नामांकन के बावजूद, कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जो उपधारा (2) के तहत नामित व्यक्ति नहीं हैं, को भी परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सकता है यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध यह अपराध "ऐसे व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण किया गया है"। [1023 बी-डी]

4. अधिनियम की धारा 17(2) का यह अर्थ लगाना कि कार्रवाई के लिए उत्तरदायी एकमात्र व्यक्ति धारा 17(2) के तहत नामित/नामांकित व्यक्ति है, धारा 17(2) के स्पष्टीकरण को पूरी तरह से भ्रामक बना देगा। [1023 ई-एफ]

5. जहां पूरे देश में बिक्री संगठन के व्यापक नेटवर्क के साथ एक बड़ा व्यावसायिक संगठन है, उसे अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को

नामित करना चाहिए या धारा 17(1)(ए)(ii) में निर्धारित परिणामों का सामना करना पड़ेगा। धारा 17(2) से जुड़ा स्पष्टीकरण इस बात पर विचार करता है कि जहां किसी कंपनी के अलग-अलग प्रतिष्ठान या शाखाएं या किसी प्रतिष्ठान या शाखा में अलग-अलग इकाइयां हैं, वह अलग-अलग प्रतिष्ठानों या शाखाओं या इकाइयों और व्यक्ति के संबंध में अलग-अलग व्यक्तियों को नामांकित कर सकती है। किसी भी प्रतिष्ठान या शाखा या इकाई के संबंध में इस प्रकार नामित व्यक्ति को ऐसे प्रतिष्ठान या शाखा या इकाई के संबंध में जिम्मेदार व्यक्ति माना जाएगा। स्पष्टीकरण की भाषा एक उद्देश्य दर्शाती है और इसलिए, उस उद्देश्य के अनुरूप एक निर्माण उचित रूप से उस पर रखा जाना चाहिए।

[1024 एफ-एच, 1025 ए]

धारा 17(2) का स्पष्टीकरण, हालांकि अनुज्ञेय शर्तों में ऐसी कंपनी पर विभिन्न प्रतिष्ठानों या शाखाओं या इकाइयों के संबंध में एक व्यक्ति को नामांकित करने का कर्तव्य लगाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका तात्पर्य सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन से है, अन्यथा, इस अनुभाग में अंतर्निहित योजना अव्यवहारिक होगी।

[1024 ए-डी]

स्पष्टीकरण उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें धारा 17(2) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। आम तौर पर, 'शब्द का अर्थ यह हो सकता है कि क्या वैकल्पिक है, लेकिन बताए गए कारणों के लिए, जिस संदर्भ में यह प्रकट होता है, उसका अर्थ 'जरूरी' होना चाहिए। मजबूरी का एक तत्व है। यह एक शक्ति के साथ कर्तव्य भी है। हालांकि कंपनी कोई निकाय या प्राधिकरण नहीं है, फिर भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि वही सिद्धांत लागू न हो। इस प्रकार यह सुझाव देना गलत है कि स्पष्टीकरण केवल एक सक्षम प्रावधान है, जब इसका उल्लंघन ऊपर बताए

गए परिणामों पर निर्भर करता है। इसे किसी की पसंद पर नहीं छोड़ा गया है, लेकिन कानून इसे अनिवार्य बनाता है। माना जाता है कि मेसर्स आनंद ओमर भोय ने अपनी दिल्ली शाखा के संबंध में फिलहाल किसी भी व्यक्ति को नामांकित नहीं किया था। इसलिए, मामला धारा 17(1)(ए)(ii) द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट है। [1024 डी-ई, एच, 1025 ए]

जूलियस बनाम ऑक्सफोर्ड के लॉर्ड बिशप, [1875-85] ए.सी. 214; अनुमोदन के साथ उद्धृत।

6. बिक्री प्रबंधक की व्यक्तिगत देनदारी निर्माता की कॉर्पोरेट देनदारी से अलग और अलग है। 'कंपनी अभियोजन' के मामले में, कंपनी और उसके एजेंट, यानी धारा 17(2) के तहत नामांकित व्यक्ति और बिक्री प्रबंधक दोनों पर धारा 16(1)(ए) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 7(1) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 17(2) के तहत जिम्मेदार व्यक्ति के नामांकन के बावजूद, धारा 17(4) के तहत कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना जरूरी है कि अपराध 'ऐसे व्यक्तियों की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उनकी ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है।' [1025 बी-डी]

आपराधिक अपीलिय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 243/1979

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 271/78 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 13-9-1978 से उत्पन्न विशेष अनुमति द्वारा अपील।

यू. आर. ललित, आर. बाना, एम. एन. श्रॉफ और मिस ए. सुभाशिनी, अपीलार्थी की ओर से।

के. एल. अरोड़ा, आर. एस. सोधी और एच. सी. गुलाटी, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वी. बी. गणात्रा, आई. एन. श्रॉफ और एच. एस. परिहार, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

सेन, न्यायाधिपति. - इस अपील में, विशेष अनुमति से, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से, दो प्रश्न उठते हैं जो बहुत सामान्य महत्व के हैं। पहला, ऐसे मामले में जहां किसी खाद्य पदार्थ का निर्माता एक कंपनी है, जिसने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 17 की उप-धारा (2) के तहत एक व्यक्ति को जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित किया है, चाहे वह इसकी किसी शाखा के बिक्री प्रबंधक पर अधिनियम की धारा 7(i) के साथ पठित धारा 16(1)(ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जब शाखा में बेची गई खाद्य सामग्री अधिनियम की धारा 2(आइए) के अर्थ में मिलावट पाई जाती है। दूसरा, क्या 1976 के अधिनियम 34 द्वारा नई धारा 17 की शुरुआत के बाद, जब किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है, जिसने धारा 17(2) के तहत जिम्मेदार व्यक्ति को नामांकित किया है, उप-धारा (2) के तहत नामित नहीं किए गए कंपनी के किसी अन्य अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है। जब तक यह आरोप न हो कि अपराध ऐसे अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया था, या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण किया गया था।

पहले प्रश्न पर तथ्य न्यूनतम संभव दिशा-निर्देश के दायरे में हैं। 23 जून 1977 को दिल्ली प्रशासन ने धारा 7(i) सहपठित धारा 6(1)(ए) और धारा 17 के तहत (1)

मेसर्स अहमद उमर भोय, अहमद मिल्स, बॉम्बे, प्रसिद्ध 'पोस्टमैन' ब्रांड या रिफाइंड मूंगफली तेल के निर्माता, (2) उनके वितरक मैसर्स गैँदा मुल हेम राज, नई दिल्ली, एक साझेदारी फर्म, और इसके प्रबंध भागीदार मेहर चंद जैन, (3) मैसर्स अमर प्रोविजन एंड जनरल स्टोर, नेताजी नगर मार्केट, नई दिल्ली और इसके मालिक अमरीक लाल, खुदरा विक्रेता, (4) वाई.ए.खान, प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण, अहमद मिल्स को निर्माताओं द्वारा अधिनियम की धारा 17(2) के तहत जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नियुक्त किये गए, और (5) दो बिक्री प्रबंधक, दिल्ली शाखा मेसर्स अहमद उमर भोय, निर्माता, आई.के.नांगिया और वाई.पी.भसीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

यह आरोप लगाया गया था कि 31 अगस्त 1976 को, नई दिल्ली नगरपालिका समिति के खाद्य निरीक्षक, एस.डी.शर्मा ने मैसर्स अमर प्रोविजन एंड जनरल स्टोर से 'पोस्टमैन' ब्रांड रिफाइंड मूंगफली तेल का एक नमूना उठाया था, जिसे इसे मैसर्स गैँदा मुल हेम राज द्वारा 20 अगस्त 1976 को को बेचा गया था, और सार्वजनिक विश्लेषक ने 9 सितंबर 1976 को अपनी रिपोर्ट में इसे 'अरंडी तेल' (खाद्य तेल नहीं) की उपस्थिति के कारण मिलावटी पाया था। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि 20 अगस्त, 1976 को मेसर्स अहमद उमर भोय द्वारा इस मिलावटी भोजन सामग्री मेसर्स गैँदा मुल हेम राज को दिल्ली में अपने बिक्री प्रबंधक, आई.के.नांगिया और वाई.पी.भसीन द्वारा आपूर्ति/बेची गई थी।

मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 1978 द्वारा पाया कि मेसर्स अहमद उमर भोय, 'पोस्टमैन' ब्रांड रिफाइंड मूंगफली तेल के निर्माता,

दिल्ली में उनके वितरकों मेसर्स गैदा मुल हेम राज और मेसर्स अमर प्रोविसन स्टोर, खुदरा विक्रेता साथ ही साथ वाई.ए.खान, गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक अहमद मिल्स के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला था। लेकिन प्रतिवादी आई.के.नांगिया और वाई.पी.भसीन, मेसर्स अहमद उमर भोय दिल्ली के दो विक्री प्रबंधक के खिलाफ कोई भी प्रक्रिया जारी करने से इनकार कर दिया यह पाते हुए कि हालांकि उन्होंने मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री की थी, लेकिन उन्हें संबंधित वस्तु के निर्माण से कोई सरोकार नहीं था, बल्कि उन्होंने केवल बिक्री को प्रभावित किया था। तदनुसार, उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका अभियोजन गलत था।

दिल्ली प्रशासन ने पुनरीक्षण के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया लेकिन इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ कोई भी प्रक्रिया जारी करने से इनकार करने का आदेश पूरी तरह से अनुचित है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि इन प्रतिवादियों ने कोई अपराध नहीं किया है और इसलिए, विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए यह निष्कर्ष निकालना खुला नहीं था कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं था। बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह ⁽¹⁾ मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण यह है कि प्रारंभिक चरण में, यदि कोई मजबूत संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तब न्यायालय के पास यह कहने का अधिकार नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था।

मौजूदा मामले में, शिकायत में लगाए गए आरोप प्रतिवादियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 16(1)(ए) के साथ पठित धारा 7(i) के तहत अपराध कारित करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। शिकायत में, वास्तविक आरोप इस प्रकार हैं:

"6. यह कि मिलावटी खाद्य सामग्री मेसर्स गैदा मुल हेम राज को 20-8-76 को मेसर्स अहमद उमर भोय द्वारा दिल्ली में इसके बिक्री प्रबंधकों आई.के.नांगिया और वाई.पी.भसीन के माध्यम से आपूर्ति/बेची गई थी।

7. यह है कि अभियुक्त वाई.ए.खान अभियुक्त नंबर 5 का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है अभियुक्त आई.के.नांगिया और वाई.पी.भसीन अभियुक्त नंबर 5 के सेल्स मैनेजर (स्थानीय शाखा) हैं और अभियुक्त संख्या 5 द्वारा अपराध किए जाने के समय इसके व्यवसाय के संचालन के लिए इसके प्रभारी और जिम्मेदार थे।"

"इसके प्रभारी थे' और "इसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार" शब्द इतने व्यापक हैं कि इसमें दिल्ली में मेसर्स अहमद कॉमर भोय की सभी व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। यह एक सामान्य आधार है कि उनका दिल्ली कार्यालय 2-ए/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली में है, और दो प्रतिवादी आई.के.नांगिया और वाई.पी.भसीन बिक्री प्रबंधक हैं।

शिकायत में एक विशिष्ट आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी दिल्ली में अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अपने नियोक्ताओं के प्रभारी थे और उनके प्रति जिम्मेदार थे। एस.डी.शर्मा, खाद्य निरीक्षक, पीडब्लू-1 ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत पूछताछ के दौरान कहा है कि संबंधित खाद्य पदार्थ की मिलावटी वस्तु उनके द्वारा वितरकों मेसर्स गैदा मुल हेम राज को बिल संख्या 62 के माध्यम से दिनांक 20 अगस्त 1976 को बेची गई थी। इसके अलावा, वह कहते हैं, कि वे उस समय दिल्ली में अपने व्यवसाय के संचालन के लिए मेसर्स अहमद उमर भोय के प्रभारी और जिम्मेदार थे।

अब, वास्तव में मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 7(i) के तहत सीधे तौर पर उत्तरदायी है, जिसमें लिखा है:

"7. कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री के लिए निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा।

(i) कोई भी मिलावटी खाद्य;"

निर्माता, मैसर्स अहमद उमर भोय, बॉम्बे उत्तरदायी बन गए क्योंकि वे दिल्ली में अपने शाखा कार्यालय के माध्यम से सीधे मिलावटी वस्तु बेच रहे थे। प्रतिवादी आई.के. नांगिया और वाई.पी.भसीन भी "अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा" शब्दों, जिसमें उनके एजेंट और नौकर शामिल हैं, के कारण उत्तरदायी बन गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अनुभाग का वास्तविक निर्माण है। इसे देखते हुए, विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उत्तरदाताओं के खिलाफ शिकायत को खारिज नहीं कर सकते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि मैसर्स अहमद उमर भोय, बॉम्बे ने 31 जुलाई, 1916 को धारा 17(2) के तहत आरोपी वाई.ए.खान, मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, अहमद मिल्स को कंपनी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त किया था। धारा 17(1)(ए)(आई) के बल पर यह तर्क दिया गया है कि इसलिए, मैसर्स अहमद उमर भोय द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रतिवादियों पर विचारण नहीं चलाया जा सकता है। हमारी राय में, इस विवाद को केवल अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। इसमें न केवल विधायिका को कुछ ऐसा जिम्मेदार ठहराना शामिल है जिसका कभी इरादा नहीं था, बल्कि यह निर्माण के सामान्य सिद्धांतों के साथ टकराव भी करता है।

प्रश्न 1976 के अधिनियम 34 द्वारा शुरू की गई नई धारा 17 के उचित निर्माण पर आता है, जहां तक सामग्री इस प्रकार है:

"17. (i) जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध एक कम्पनी द्वारा किया गया है।

(क) (i) वह व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसे उप-धारा (2) के तहत कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार होने के लिए नामित किया गया है (इसके बाद इस अनुभाग में इसे पुनः उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया है), या

(ii) जहां किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था; और

(ख) कंपनी,

अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम में प्रदान की गई किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित प्रयास किए थे।

(2) कोई भी कंपनी, लिखित आदेश से, अपने किसी भी निदेशक या प्रबंधक (ऐसे प्रबंधक जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत हैं) को ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और कंपनी द्वारा

इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध को करने से रोकने के लिए आवश्यक या समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत कर सकती है और स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से नोटिस दे सकती है जो निर्धारित किया जा सकता है, कि उसने ऐसे निदेशक या प्रबंधक को जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित किया है, साथ ही इस तरह नामित होने के लिए ऐसे निदेशक या प्रबंधक की लिखित सहमति भी शामिल है।

स्पष्टीकरण - जहां किसी कंपनी के अलग-अलग प्रतिष्ठान, या शाखाएं या किसी प्रतिष्ठान या शाखा में अलग-अलग इकाइयां हैं, वहां अलग-अलग प्रतिष्ठानों या शाखाओं या इकाइयों के संबंध में इस उपधारा के तहत अलग-अलग व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है और किसी भी प्रतिष्ठान, शाखा के संबंध में नामित व्यक्ति को नामित किया जा सकता है। या इकाई को ऐसे प्रतिष्ठान, शाखा या इकाई के संबंध में जिम्मेदार व्यक्ति माना जाएगा।

(3) x x x x x x

(4) पूर्वगामी उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि अपराध उसकी सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, [उपधारा (2) के तहत नामांकित व्यक्ति नहीं] किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है। ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का

दोषी माना जाएगा और किया जाएगा। उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।"

धारा के स्पष्ट अर्थ में, जब किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, जहां धारा 17(2) के तहत कोई नामांकन नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के संचालन हेतु व्यवसाय के प्रति जिम्मेदार था, अपराध का दोषी माना जाता है और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और दंडित किया जा सकता है। धारा 17(2) के तहत किसी व्यक्ति के नामांकन के बावजूद, कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी [उप-धारा (2) के तहत नामांकित व्यक्ति न होते हुए] को भी परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सकता है यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध 'उस व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण है'।

हालाँकि, यह आग्रह किया गया है कि कंपनी ने आरोपी वाई.ए.खान, गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक, अहमद मिल्स को धारा 17(2) के तहत जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित किया है, वह एकमात्र उत्तरदायी व्यक्ति है पूरे देश में इसके विरुद्ध कार्यवाही करना और प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाना पूरी तरह से गलत धारणा है। हमारा ध्यान नामांकन फॉर्म की ओर गया है और इसमें कहा गया है कि वह कंपनी के लिए जिम्मेदार होंगे। हमें डर है, इस विवाद में कोई दम नहीं है. दस्तावेज़ में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि नामांकन न केवल बॉम्बे में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के लिए बल्कि विभिन्न राज्यों में इसकी सभी शाखाओं के लिए भी प्रभावी है। हमारी राय में, ऐसा निर्माण धारा 17(2) के स्पष्टीकरण को पूरी तरह से भ्रामक बना देगा।

जहां पूरे देश में बिक्री संगठनों के व्यापक नेटवर्क वाला एक बड़ा व्यावसायिक संगठन है, उसे अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को नामित करना चाहिए या धारा 17(1)(ए)(ii) में निर्धारित परिणामों का सामना करना पड़ेगा। धारा 17(2) से जुड़ा स्पष्टीकरण इस बात पर विचार करता है कि जहां किसी कंपनी के अलग-अलग प्रतिष्ठान या शाखाएं या किसी प्रतिष्ठान या शाखा में अलग-अलग इकाइयां हैं, वह अलग-अलग प्रतिष्ठानों या शाखाओं या इकाइयों के संबंध में अलग-अलग व्यक्तियों को नामांकित कर सकती है। और किसी प्रतिष्ठान या शाखा या इकाई के संबंध में इस प्रकार नामित व्यक्ति को ऐसे प्रतिष्ठान या शाखा या इकाई के संबंध में जिम्मेदार व्यक्ति माना जाएगा। स्पष्टीकरण की भाषा एक उद्देश्य दर्शाती है और इसलिए, उस उद्देश्य के अनुरूप एक निर्माण उचित रूप से उस पर रखा जाना चाहिए।

हमें स्पष्ट हैं कि धारा 17(2) का स्पष्टीकरण, हालांकि अनुमति के संदर्भ में, ऐसी कंपनी पर विभिन्न प्रतिष्ठानों या शाखाओं या इकाइयों के संबंध में एक व्यक्ति को नामांकित करने का कर्तव्य लगाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका तात्पर्य सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन से है, अन्यथा, इस अनुभाग में अंतर्निहित योजना अव्यवहारिक होगी। हमारी राय में, मामला जूलियस बनाम ऑक्सफोर्ड के लॉर्ड बिशप

(1) मामले में लॉर्ड कैरीस के आदेश के अंतर्गत आता है:

"जिस चीज को करने का अधिकार दिया गया है उसकी प्रकृति में कुछ हो सकता है, जिस उद्देश्य के लिए यह किया जाना है उसमें कुछ हो सकता है, उन परिस्थितियों में कुछ हो सकता है जिनके तहत यह किया जाना है, उन व्यक्तियों के शीर्षक में कुछ हो सकता है जिनके लाभ के लिए यह किया गया है शक्ति का प्रयोग किया जाना है, जो

शक्ति को एक कर्तव्य के साथ जोड़ सकता है, और उस व्यक्ति का कर्तव्य बना सकता है जिसमें शक्ति सौंपी गई है कि जब ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वह उस शक्ति का प्रयोग करे।”

स्पष्टीकरण उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें धारा 17(2) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। आम तौर पर, 'हो सकता है' शब्द का अर्थ वैकल्पिक है, लेकिन बताए गए कारणों से, जिस संदर्भ में यह प्रकट होता है, उसका अर्थ 'जरूरी' होना चाहिए। मजबूरी का एक तत्व है। यह शक्ति के साथ कर्तव्य भी है। मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, 11 वें संस्करण में पृष्ठ 231 पर, सिद्धांत इस प्रकार बताया गया है:

"कानून जो व्यक्तियों को दूसरों के लाभ के लिए कार्य करने के लिए अधिकृत करते हैं, या, जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है, जनता की भलाई या न्याय की उन्नति के लिए, प्राधिकार प्रदान करते समय अक्सर यह विवाद उत्पन्न हो गया है कि यह केवल सक्षम करने योग्य है और अनिवार्य नहीं है। यह अधिनियमित करने में कि वे "कर सकते हैं" या "करेंगे, यदि वे उचित समझें", या, "उनके पास शक्ति होगी", या यह कि उनके लिए ऐसे कार्य करना "वैध होगा", एक कानून मात्र अनुमति की भाषा का उपयोग करता प्रतीत होता है, लेकिन यह अक्सर निर्णय लिया गया है कि यह एक सिद्धांत बन गया है कि ऐसे मामलों में ऐसी अभिव्यक्तियां - कम से कम कर्तव्य - एक अनिवार्य बल

हो सकती हैं, और इसलिए न्यायिक व्याख्या द्वारा संशोधित किया जा सकता है।” (जोर दिया गया)।

हालाँकि कंपनी कोई निकाय या प्राधिकरण नहीं है, फिर भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि वही सिद्धांत लागू न हो। इस प्रकार यह सुझाव देना गलत है कि स्पष्टीकरण केवल एक सक्षम प्रावधान है, जब इसका उल्लंघन ऊपर बताए गए परिणामों पर निर्भर करता है। इसे किसी की पसंद पर नहीं छोड़ा गया है, लेकिन कानून इसे अनिवार्य बनाता है। माना जाता है कि मेसर्स अहमद उमर भोय ने अपनी दिल्ली शाखा के संबंध में फिलहाल किसी भी व्यक्ति को नामांकित नहीं किया था। इसलिए, मामला पूरी तरह से धारा 17(1)(ए)(ii) के अंतर्गत आता है।

तैयार किए गए दो प्रश्नों पर, उत्तर स्वयं स्पष्ट है। बिक्री प्रबंधक की व्यक्तिगत देनदारी निर्माता की कॉर्पोरेट देनदारी से अलग और अलग है। 'कंपनी अभियोजन' के मामले में, कंपनी और उसके एजेंट, यानी धारा 17(2) के तहत नामांकित व्यक्ति और बिक्री प्रबंधक दोनों पर धारा 16(1)(ए) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 7(i) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 17(2) के तहत जिम्मेदार व्यक्ति के नामांकन के बावजूद, धारा 17(4) के तहत कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना जरूरी है कि अपराध 'उस व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है।'

परिणाम, इसलिए, यह है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का आदेश अपास्त किया जाता है और उसे प्रतिवादियों को समन जारी करने और कानून के अनुसार विचारण की कार्यवाही करने निर्देश दिया जाता है।

वी.डी.के

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।